Complaints against custom officers

1965. SHRI KRISHAN KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain complaints from the Environment Ministry against the customs officials have been received alleging their involvement in the illegal trade in the endangered flora and fauna including the illegal transportation of large segments of Finances and Munias;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the outcome of the inquiry made by the Government; and

(d) what action has been taken by Government against those identified in the illegal trade?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) The Ministry of Environment and Forests have referred to this Ministry only one case involving release of 'Shahtoosh' by customs officials at the Delhi Airport. It has been pointed out that trade in 'Shahtoosh' is banned under the Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora' and the circumstances under which the above release was made would need to be looked into.

(c) and (d) Investigation in the above case is in progress. Notices have been issued to the importers, who are of Nepali origin. The importers are, however, not traceable.

National Housing Bank without Chairman

1966. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Housing Bank (NHB) is working without full time Chairman since more than last two years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what are the reasons for the major lapses for bank's gradually declining business as compared to earlier years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) Steps have been initiated for filling up the vacancy of Chairman and Managing Director, National Housing Bank.

(c) National Housing Bank has reported that the decline in the business of the bank was mainly on account of paucity of resources. In view of changes in the interest rates structure, the cost of funds had also increased. Further, with housing finance companies having able to mobilise substantial resources on their own they are depending less on the National Housing Bank for funds.

ढाका में हुई "दक्षेस" की बैठक

1967. **श्री अन्नतराम जायसवाल :**
श्री दिग्विजय सिंह :
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1994 के पहले सप्ताह में ढाका में "दक्षेस" देशों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया और उन पर क्या निर्णय लिए गए क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हाँ दक्षेस वित्त मंत्रियों का सम्मेलन 10–11 जुलाई, 1994 को आयोजित हुआ।

(ख) सम्मेलन में निर्धनता विरोधी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। मंत्रियों ने क्षेत्रीय आधार पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर ध्यान दिए जाने की मूल आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति में अपनाई गई प्रवृत्तियों की समीक्षा की और क्षेत्रीय सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीयवाद में वृद्धि की प्रवृत्ति पर सन्तुष्टि व्यक्त की। मंत्रियों ने आगे आभास किया कि दक्षेस के आंतरिक देशों के व्यापार को विस्तार दक्षेस देशों को एक साथ और अधिक समीप लाएगा और उनकी आर्थिक समृद्धि में सहायक होगा। उन्होंने बल दिया कि सुधार कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन पर त्वरित प्रयासों में सहायक होने चाहिए जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि अल्प काल में उनका निर्धन लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता। मंत्रियों ने यह सहमति व्यक्त की कि एक त्रीस्तरीय कार्यविधि स्थापित की जानी चाहिए जो निर्धनता को कम किए जाने की क्रियान्वयन में दक्षेस देशों के अनुभवों पर सूचना के विनिमय के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक बोर्ड

1968. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंक में गैर-सरकारी निदेशक बोर्ड गठित करने का मामला किस चरण में है और इस तरह के गठन की पूरी प्रक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्तियां राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 और 1980 में दिए गए मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं। इन कानूनों के अनुसार इन निदेशकों की नियुक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती हैं।

सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Tax benefits for handicapped people

1969. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to extend more Income Tax exemption benefits for handicapped people;

(b) what are the details of the representation received by Government from associations representing handicapped people;

(c) what is the reaction of Government;

(d) whether it is a fact that handicapped people get income-tax benefits in other countries;

(e) whether Government would also extend Income Tax benefits to business units patronizing activities and sports of handicappel people; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Government receives representation from time to time from various associations representing handicapped people for extending the scope of the tax concessions available to handicapped persons. Responding to these suggestions, the scope of several tax concessions have been enlarged.